I.L.R. Punjab and Haryana

अमर बीर सिंह गिल जे. के समक्ष

आनंद सिंह डांगी,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य- प्रतीयार्थी

CRIMINAL MISC. 2000 का नंबर 16172/M

8जून, 2000

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 438- भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा. 218, 406, 409, 418, 420, 467, 471 और 120- ख- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धारा 13 (i) (घ)- विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 1954- धारा 2 (ङ)-. 1954 के अधिनियम के तहत गैर-हकदार व्यक्तियों को भूमि आबंटन में स्पष्ट अनियमितताओं/ अवैधताओं के आरोपों पर हरियाणा के राजस्व मंत्री और अन्य-मंत्री के ख़िलाफ़ FIR- मंत्री अपने चहेतों को आबंटन की मंजूरी दे रहे हैं- अपने आधिकारिक दर्जे का दुरुपयोग करके राज्य को गलत नुकसान पहुंचाया और आय के अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक बेनामी संपत्ति अर्जित की-1954 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किए गए नकली आबंटन- ऐसी जानकारी और सामग्री एकत्र करने के लिए ऐसे अभियुक्तों की अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक है जो अन्यथा छिपी रहेगी- पूर्व मंत्री अग्रिम जमानत की रियायत के हकदार नहीं हैं। -आपराधिक साजिश में भागीदार होने वाले अन्य आरोपी भी इस तरह की रियायत के लायक नहीं हैं- याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने कथित रूप से विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के आबंटन के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं को अनदेखा किया और कथित रूप से करोड़ों रुपये एकत्र किए।इन सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ परस्पर *संबंध* दिखाने वाले आरोपों और वे आपराधिक साजिश में भागीदार होने के कारण, अग्रिम जमानत में रियायत के उद्देश्य से उनके मामलों पर संदर्भ से बाहर विचार करना सुरक्षित नहीं है।एफ. आई. आर. में निहित आरोप शेष तीन याचिकाकर्ताओं के मामलों को उनके अन्य सहयोगियों से उनके द्वारा कथित रूप से संयुक्त रूप से किए गए अपराधों के लिए अलग करने का आह्वान नहीं करते हैं।उनकी अभिरक्षा में पूछताछ यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि उनके पक्ष में वकीलों की सामान्य शक्तियों को किसने निष्पादित किया था और उनके द्वारा वकीलों की इन शक्तियों को कहां प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जालसाजी की गई थी और यह भी पता लगाने के लिए कि

सहायक पंजीयक अपने दावे की शुद्धता या वकीलों की शक्ति की पुष्टि नहीं करके झूठे मामलों को संसाधित करने के उनके मंसूबों का शिकार कैसे हुआ।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के अलावा आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक बेनामी संपत्ति जमा करने, उस राज्य को धोखा देने के हैं जिसके हितों की रक्षा करने के लिए वह कर्तव्यबद्ध था, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करना जो जाली थे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार आदि। ये सभी गंभीर अपराध हैं।आपराधिक साजिश का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हो सकता है और इसी तरह के मामलों में आरोपी व्यक्तियों के कृत्यों और आचरण से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए।ऐसे अभियुक्तों की अभिरक्षा में पूछताछ जानकारी और ऐसी सामग्री एकत्र करने के लिए आवश्यक है जो अन्यथा छिपी रहती है।उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आरोपी व्यक्तियों को इस तरह की रियायत के लिए कुछ बहुत ही मजबूर करने वाली परिस्थितियां नहीं बनाई जाती हैं।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ता की ओर से एच. एस. हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुरमीत कौर के साथ और अधिवक्ता बलदेव सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता अमनदीप सिंह के साथ,

एम. एल. सरीन, ए. जी. हरियाणा अमरजीत सिंह के साथ, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा-राज्य के लिए।

निर्णय

अमर बीर सिंह गिल, जे.

(1) यह आदेश 2000 की आपराधिक विविध याचिकाओं 16172-एम, 16156-एम, 16963-एम और 16968-एम का निपटारा करेगा क्योंकि इन सभी चार मामलों में याचिकाकर्ता एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 3 में आरोपी हैं। दिनांक 8 अप्रैल, 2000 को भारतीय दंड संहिता की धारा 218, 406, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (i) (डी) के तहत पुलिस स्टेशन, राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला रेंज, अंबाला में पंजीकृत किया गया। याचिकाकर्ताओं को उक्त मामले में उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों पर गिरफ्तार करने की मांग की गई है, जो निम्नानुसार है

"एस. एच. ओ., राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला को।महोदय, वित्तीय आयुक्त-सह-सचिव, सतर्कता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा 7 मार्च, 2000 को जारी किए गए जांच ज्ञापन के संयोजन में जांच, जिसके तहत *एक* मामला दर्ज किया गया है, निदेशक सतर्कता हरियाणा द्वारा आर. के. बच्चन, आई. पी. एस., आई. जी., सतर्कता, हरियाणा, चंडीगढ़ को सौंप दी गई है।यह जांच 26 नवंबर, 1999 को हरियाणा सरकार के विशेष सचिव पुनर्वास विभाग द्वारा जारी यू. ओ. संख्या 12687/ए. आर. एच. पर आधारित है।उक्त यू. ओ. में आरोप थे कि पुनर्वास विभाग

द्वारा 1 जनवरी, 1995 से 21 जून, 1996 तक 172 मामलों में अलग-अलग व्यक्तियों को 1329 एकड़ भूमि गलत तरीके से आवंटित की गई है।172 मामलों में से 32 मामलों में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अनदेखा किया और सीधे तहसीलदार अंबाला से फाइल तलब की और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके आबंटन प्राप्त किया।आरोप की जांच के दौरान, यह पाया गया कि हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग ने 1 जनवरी, 1995 से 21 जून, 1996 तक विभिन्न स्थानों पर 95 व्यक्तियों को 1405 एकड़ और 14 मरला भूमि आवंटित की है।जाँच के दौरान यह पाया गया है कि लगभग सभी मामलों में जो भी व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित हुआ, उसने अपनी भूमि का दावा दायर किया, उसके दावे की ठीक से पुष्टि नहीं हुई।कुछ मामलों में वास्तविक दावेदार को मृत दिखाया गया है और किसी अन्य व्यक्ति ने खुद को मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी बताते हुए दावा दायर किया है।ऐसे सभी मामलों में, यह पाया गया है कि एल. आर. ने केवल मृतक के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए अपना हलफनामा दायर किया है।श्री दीदार सिंह, तहसीलदार मुख्यालय और ए. आर.

हलफनामे और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दावेदारों के दावों का फैसला किया गया और तहसीलदार सेल्स, अंबाला को यूओ जारी किया गया।श्री दीदार सिंह ने यू. ओ. जारी करने से पहले मृतक के एल. आर. का सत्यापन नहीं किया। जगदीश राय, तहसीलदार सेल्स-कम-एम. ओ. अंबाला ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले संबंधित व्यक्ति को आबंटन चिट जारी की।आबंटन चिट जारी करने से पहले, आबंटन प्रस्ताव श्रीमती अनती रानी द्वारा तैयार किया गया था, आबंटन कानूनगो और आबंटन प्रस्ताव तत्कालीन तहसीलदार जगदीश शर्मा द्वारा स्वीकार किया गया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री आनंद सिंह डांगी को फाइल भेजी गई थी।जांच में पता चला है कि लगभग सभी मामलों में आबंटन की अनुमति श्री जगदीश शर्मा ने उसी तारीख को जारी की थी, फाइल आनंद सिंह डांगी ने देखी थी।श्री आनंद सिंह डांगी ने इन सभी फाइलों को सीधे तहसीलदार बिक्री श्री जगदीश शर्मा से तलब किया, जबकि इसे हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव पुनर्वास विभाग के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए था।जांच में पता चला है कि 24 मामलों में से 10 मामलों में शांति सरूप जाति के बढ़ई के बेटे ईश्वर चंद, दो मामलों में अमीन चंद पूर्व सरपंच के बेटे नरेंदर और एक मामले में नरेंदर के भाई सतीश कुमार बनाम उज्जला जिला।अंबाला के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है।जाँच मे पता चलल अछि जे श्री।तत्कालीन राजस्व मंत्री आनंद सिंह डांगी ने दीदार सिंह, तहसीलदार बिक्री, मुख्यालय हरियाणा, चंडीगढ़, जगदीश राय तहसीलदार (सेवानिवृत्त) बिक्री, अंबाला, नरेंद्र पुत्र अमीन चंद, ईश्वर पुत्र शांति सरूप, सतीश पुत्र अमीन चंद के साथ साजिश में अपने पद का दुरुपयोग किया और खुद को और अन्य फर्जी आबंटनकर्ताओं को गलत लाभ देने के उद्देश्य से सीधे जगदीश राय, तहसीलदार अंबाला से फाइलों को कॉल करके अपने पसंदीदा लोगों को किए गए आबंटन को मंजूरी दी।श्री आनंद सिंह डांगी यह अच्छी तरह से जानते थे कि राज्य के हितों की रक्षा करने के बजाय वे

वकीलों की फर्जी शक्तियों के आधार पर फर्जी आबंटनकर्ताओं को गलत लाभ दे रहे थे और तहसीलदार बिक्री कार्यालय के कर्मचारियों को फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मजबूर कर रहे थे और इस तरह राज्य सरकार को गलत तरीके से करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा था और दुर्भावनापूर्ण तरीके से फर्जी दस्तावेज का असली के रूप में इस्तेमाल किया और इस प्रकार उपरोक्त पूर्व ने कहा। मंत्री आनंद सिंह डांगी, दीदार सिंह तहसीलदार सेल्स, अंबाला (सेवानिवृत्त) नरेंदर सिंह, नरिश कुमार पुत्र अमीन चंद, ईश्वर पुत्र शांति सरूप को पी. सी. अधिनियम 1988 की धारा 13 (आई) (डी) के साथ आई. पी. सी. की धारा *218,406,409,418,420,467,468,471,120-बी के तहत अपराध करते हुए पाया गया और इसके परिणामस्वरूप जांच रिपोर्ट हरियाणा सरकार को भेजी गई जिसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का सुझाव दिया गया और अब,*

सरकारी पत्र सं. 30 मार्च, सतर्कता (i) दिनांक 7 मार्च, 2000 को उपरोक्त अपराधों के तहत उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ है।मामला दर्ज होने के बाद मामले के रिकॉर्ड के साथ जांच फाइल को एस. पी. विजिलेंस, अंबाला को सौंप दिया जाए।एफ. आई. आर. की प्रतियां प्रभारी मजिस्ट्रेट अंबाला और उच्च अधिकारियों को भेजी जाएं।इन 24 मामलों के अलावा, अन्य कई मामलों में भूमि का फर्जी आबंटन किया गया है।उसी तरह जांच की जाए।एस. डी./- डी. एस. पी. सतर्कता, अंबाला दिनांक 8 अप्रैल, 2000।"

(2)उस समय आनंद सिंह दांगी हरियाणा के राजस्व मंत्री थे।

एफ. आई. आर. में निहित आरोपों के अनुसार, 1 जनवरी, 1995 से 21 जून, 1996 तक 172 मामलों में पुनर्वास विभाग द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को गलत तरीके से 1329 एकड़ भूमि आवंटित करने में उनकी भूमिका थी और 172 मामलों में से 32 मामलों में उन्होंने तहसीलदार बिक्री, अंबाला से सीधे फाइलों को बुलाकर भूमि आबंटन के लिए निषिद्ध प्रक्रिया को अनदेखा किया और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके आबंटन प्राप्त किया।1 जनवरी, 1995 से 21 जून, 1996 तक विभिन्न स्थानों पर 94 व्यक्तियों को 1405 एकड़ और 14 मरले की भूमि आवंटित की गई थी और लगभग सभी मामलों में जो भी खुद को पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति होने का दावा करता है, उसने भूमि के आबंटन के लिए दावा दायर किया था, उसके दावे की ठीक से पुष्टि नहीं हुई थी।कुछ मामलों में वास्तविक दावेदार को मृत दिखाया गया था और किसी अन्य व्यक्ति ने मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दावा दायर किया था।ऐसे सभी मामलों में, दावा कथित रूप से कानूनी प्रतिनिधियों के हलफनामों के आधार पर दायर किया गया था।आबंटन प्रस्ताव किए जाने के बाद, फाइल सीधे आनंद सिंह डांगी को भेजी गई और उन्होंने आबंटन की हर फाइल पर अपना समर्थन दिया और उसी दिन आबंटन चिट्स जारी किए गए।आनंद सिंह डांगी ने इन सभी फाइलों को सीधे तहसीलदार बिक्री से तलब किया, जबकि फाइलों को हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग के संयुक्त सचिव के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए था।यह पाया गया कि 24 मामलों में से दस मामलों में शांति सरूप के बेटे ईश्वर चंद, दो मामलों में सरपंच अमीन चंद एक्स के बेटे नरिंदर कुमार, (आपराधिक विविध मामलों

में याचिकाकर्ता।2000 का सं. 16968 एम) और एक मामले में उपरोक्त नरिंदर कुमार के भाई सतीश कुमार के पास मुख़्तारनामा थीं।जाँच के दौरान, यह पाया गया कि यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह राज्य के हित के खिलाफ था, आनंद सिंह डांगी ने दीदार सिंह, तहसीलदार बिक्री, जगदीश राय तहसीलदार बिक्री, अंबाला, नरिंदर, ईश्वर चंद और सतीश के साथ साजिश में अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया और खुद को और अन्य फर्जी आबंटनकर्ताओं को गलत लाभ देने के लिए सीधे इन अधिकारियों से फाइलों को कॉल करके अपने पक्ष में आबंटन किया। ।उन्होंने जाली शक्ति के आधार पर आबंटियों को गलत लाभ की अनुमति दी
वकीलों ने तहसीलदार बिक्री से फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया और इस तरह राज्य सरकार को गलत नुकसान पहुंचाया।

(3)याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी का दावा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री, जो व्यक्तिगत रूप से उनके विरोधी हैं, के हाथों राजनीतिक उत्पीड़न के कारण उन्हें उपरोक्त मामले में गलत तरीके से शामिल किया जा रहा है।इस याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि उन्होंने फरवरी, 1990 में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के ख़िलाफ़ महम विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था और कथित उपचुनाव में धोखाधड़ी के कारण चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था।मई, 1990 के महीने में फिर से उन्होंने श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ उपचुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार, उक्त उपचुनाव लड़ने वाले आमिर सिंह की हत्या कर दी गई थी, इसलिए उपचुनाव फिर से रद्द कर दिया गया और हत्या की इस घटना के लिए याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी और उनके भाई को हमलावरों के रूप में नामित किया गया और जब पुलिस श्री ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर उन्हें उनके घर पर गिरफ्तार करने आई, तो उन्हें उनके घर में मारने का प्रयास किया गया।पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप उनके नौकर किशन चंद और दो अन्य लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई घायल हो गए।भारत सरकार ने आमिर सिंह की हत्या की घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया।माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. एन. सैकिया को जांच आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने पुलिस और श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।हालाँकि, कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई और अंततः, याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी ने एक रिट याचिका दायर कर जांच रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की।

(4)याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी का आगे का मामला यह है कि एफ. आई. आर. में कथित रूप से भूमि के अवैध आबंटन के आरोप का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भूमि के आबंटन के दावों को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वसन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 (ई) के तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना था और ऐसे अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अर्ध न्यायिक प्रकृति के थे जो अपील योग्य, पुनर्विचार *योग्य थे* और यहां तक कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वतः सुधार भी किया जा सकता था।यदि अधिकारियों द्वारा कुछ अवैध या गलत आदेश पारित किए गए थे, तो उस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति के लिए उपाय अधिनियम के तहत ही उपलब्ध है।आनंद सिंह डांगी ने आगे दावा किया कि उन्होंने

भूमि के किसी भी आबंटन से संबंधित कोई आदेश पारित नहीं किया है और विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के आबंटन के आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित किए गए हैं।उन्होंने आगे दावा किया कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने इस तरह के आबंटन से अवैध या अनधिकृत लाभ प्राप्त किया है।अंत में यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम ज़मानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

लेकिन उनके आवेदन खारिज कर दिए गए।आनंद सिंह डांगी के मामले में 10 मई, 2000 को पारित इस तरह के आदेश की एक प्रति आपराधिक विविध नंबर 2000 का सं. 16172-एम रिकॉर्ड पर अनुलग्नक पी-2 के रूप में उपलब्ध है।

(5)शेष तीन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि नरिंदर कुमार जिसके पास मुख्तारनामा था ने ने भूमि के आबंटन के लिए दावा करने को प्राथमिकता दी।उनके भाई हरीश कुमार (आपराधिक विविध संख्या 16956-एम 2000 में याचिकाकर्ता) ने भी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दावा दायर किया, जबकि ईश्वर चंद, जो एक चालक थे, ने भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर भूमि के आबंटन के लिए दावा दायर किया, जबकि राजिंदर कृष्ण (आपराधिक विविध संख्या 16963 एम 2000 में याचिकाकर्ता) शुरू में जुलाई, 1995 से 31 दिसंबर, 1995 तक सहायक पंजीयक-सह-तहसीलदार बिक्री मुख्यालय, चंडीगढ़, दीदार सिंह के रीडर के रूप में काम कर रहे थे और दीदार सिंह के सेवानिवृत्त होने पर, याचिकाकर्ता राजिंदर कृष्ण ने 15 जनवरी, 1996 से 2 जून, 1997 तक सहायक पंजीयक के रूप में काम किया।इस अवधि के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए कई दावों पर बहुत जल्दबाजी में कार्रवाई की गई और दावेदारों की पात्रता और पहचान के सत्यापन के बिना और न ही उनके सामान्य वकील के साथ दावेदारों के संबंधों का सत्यापन किया गया।याचिकाकर्ता राजिंदर कृष्ण का सहायक पंजीयक के रूप में तैनात होने के कारण इन सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक था।

(6)इन सभी याचिकाओं में जारी नोटिस के जवाब में, राज्य ने केवल आनंद सिंह डांगी द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने का फैसला किया।जवाब में, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता आनंद सिंह ने हरियाणा के राजस्व मंत्री रहते हुए अपने पक्ष में आबंटन को मंजूरी देने के लिए सीधे तहसीलदार के कार्यालय से फाइलें मंगाईं और इस तरह राज्य और वास्तविक दावेदारों को गलत नुकसान पहुंचाया और खुद गलत तरीके से हासिल किया।यह आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता वास्तव में पूरे 'रैकेट' का प्रमुख था, जिसमें दीदार सिंह, तहसीलदार सेल्स, चंडीगढ़, जगदीश राय, तहसीलदार सेल्स, अंबाला, अमीन चंद का बेटा नरिंदर, शांति स्वरूप का बेटा ईश्वर और अमीन चंद का बेटा सतीश शामिल थे।जाँच के दौरान पाया गया कि 1 जनवरी, 1995 से 21 जून, 1996 की अवधि के दौरान 172 मामलों में 1329 एकड़ भूमि गलत तरीके से आवंटित की गई थी और ऐसे 32 मामलों में याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी ने अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों को दरकिनार किया था और फर्जी व्यक्तियों के नाम पर अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करके आबंटन प्राप्त किया था।उस

ओर से जवाब में विशिष्ट उदाहरण उद्धृत किए गए हैं।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गंगी बाई, जय सिंह, जी. डी. शर्मा और श्याम सुंदर के मामलों में तहसीलदार बिक्री द्वारा याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी को फाइलें जमा करने के बाद ही आबंटन किया गया था।इसके अलावा दावों का हस्तांतरण किया गया और उनकी इच्छा के अनुसार वहां भूमि का आबंटन किया गया।

(7)यह भी कहा गया कि यह भी पता चला कि हरीश कुमार और नरिंदर कुमार, जो भाई हैं, ने अपने पक्ष में जाली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सफलतापूर्वक भूमि का आबंटन प्राप्त किया और राजिंदर कृष्ण तहसीलदार सेल्स ने उनके पक्ष में भूमि आबंटन के मामलों पर कार्रवाई करते समय दावेदारों की पात्रता के साथ-साथ उनकी पहचान और रिश्ते को भी सत्यापित नहीं किया।

(8)आरोपों के अनुसार, यह वर्ष 1995 में था कि कुछ व्यक्ति अचानक आगे आए और अपने असंतुष्ट दावों के संबंध में भूमि के आबंटन के लिए प्रबंध अधिकारी के समक्ष अपना दावा दायर किया और कुछ मामलों में चूंकि पूर्ववर्ती राजस्व मंत्री के आदेशों के तहत लगाई गई विशेष कटौती को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, इसलिए भूमि के संबंध में दावे दायर किए गए थे क्योंकि पहले विशेष कटौती लागू थी।इन मामलों को पुनर्वास विभाग के अधिकारियों द्वारा, जो इस मामले में आरोपी हैं, जल्दबाजी में और हकदारी, दावेदारों की पहचान या मूल दावेदारों के साथ उनके संबंधों के उचित सत्यापन के बिना संसाधित किया गया था।बल्कि कुछ मामलों में, बिना कोई सत्यापन किए भी दावों का निपटारा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के पक्ष में किया गया था।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि 1329 एकड़ भूमि अवैध रूप से आवंटित की गई थी और यह पता चला कि एफ. आई. आर. में नामित व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश के अनुसरण में काम किया, जो तत्कालीन राजस्व मंत्री आनंद सिंह डांगी के कहने पर रची गई थी।इसके परिणामस्वरूप, अवैध, अनियमित और नकली आबंटन गलत लाभ कमाने और दावों को गढ़कर और अवैध आबंटन के आधार पर राज्य को गलत नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए थे।

(9) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। यह प्रविष्ट है कि याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी 1995 और 1996 में राजस्व मंत्री थे जब पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया गया था।एम. एल. ए., श्री ओ. पी. बेरी ने हरियाणा विधानसभा में पुनर्वास विभाग द्वारा भूमि आबंटन के मामले में अनियमितताओं के बारे में सवाल उठाया था।बाद में, मुख्यमंत्री के रूप में श्री बंसी लाई के नेतृत्व में अगली सरकार वर्ष 1996 में सत्ता में आई।मामला फिर से उत्तेजित हो गया और परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के आदेश पर अंबाला डिवीजन के आयुक्त श्री भगवती प्रसाद द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई।आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ अनियमितताओं और आधिकारिक शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के उदाहरणों की ओर इशारा किया जैसा कि जवाब में संकेत दिया गया है।आयुक्त ने मामले-वार जाँच की और पाया कि कुछ व्यक्ति और उनके वकील दावों से पूरी

तरह से असंबद्ध हैं वो भी घटनास्थल पर उपस्थित हुए।इनमें से कुछ वकील कई मामलों में सामान्य है और विधिक प्रतिनिधि का कोई उचित सत्यापन नहीं किया गया था। न तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए और न ही कोई अन्य सत्यापन मांगा गया और न ही सुरक्षित किया गया।उन्होंने आगे रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि भूमि का आबंटन बिक्री इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में किया गया था, जो उन बिक्री इकाइयों से अलग थी जिनके तहत दावेदार रहता था।यहां तक कि एक बिक्री इकाई से दूसरी बिक्री इकाई में दावे को स्थानांतरित करते समय मुख्य निपटान आयुक्त की मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी और इस बात का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन राजस्व मंत्री आनंद सिंह डांगी ने तहसीलदार (बिक्री)-सह-प्रबंध अधिकारी, अंबाला से फाइलें क्यों मंगाई थीं।उन्होंने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि, "यह मान लेना गलत नहीं होगा कि इन मामलों में आबंटन में 'रैकेट' जैसी कार्रवाई की गई थी।" श्री ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में आने से बहुत पहले उपरोक्त जांच की गई थी और याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी का यह आरोप कि उन्हें वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पीड़ित किया जा रहा है, केवल आरोप ही बना हुआ है।वर्ष 1995 और 1996 में बार-बार राज्य सरकार के समक्ष जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 1995 से आबंटन के लिए आंदोलन किया जा रहा था। यह प्रविष्ट है कि याचिकाकर्ता जब तक कि उसके पास कुछ वैध कारण न हों आदेश पारित करने या आबंटन दावों को स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों के पदानुक्रम में नहीं आता था, लेकिन आनंद सिंह डांगी ने राजस्व मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में प्रत्येक आबंटन फाइल को लिए बुलाया और प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसके बाद उसी तारीख को आबंटन किया गया था।ऐसा ही एक मामला जय सिंह का है।उन्हें तहसीलदार बिक्री द्वारा 8.12/1/2 मानक एकड़ की सीमा तक अतिरिक्त क्षेत्र आवंटित किया गया था और 3 नवंबर, 1995 के उनके आदेश द्वारा तत्कालीन राजस्व मंत्री आनंद सिंह डांगी द्वारा अनुमति के अनुसार दावा अंबाला जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था।हालाँकि, संयुक्त सचिव, पुनर्वसन ने 6 नवंबर, 1995 को निर्देश दिया कि हस्तांतरण आवेदन को अंबाला जिले में उपलब्ध भूमि के विवरण के साथ रखा जाए।लेकिन यह मामला उनके सामने कभी नहीं रखा गया और 13 नवंबर, 1995 को यू. ओ. जारी किया गया कि माननीय राजस्व मंत्री की इच्छा के अनुसार बिक्री इकाई में आबंटित व्यक्ति को 8.12/1/2 मानक एकड़ का क्षेत्र प्रदान किया जाए।तहसीलदार सेल्स अंबाला द्वारा 15 नवंबर, 1995 के उनके नोट के अनुसार मामला आनंद सिंह डांगी याचिकाकर्ता को सीधे प्रस्तुत किया गया था और यह आबंटन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था।इसी तरह, श्याम सुंदर के मामले में, देवी डिट्टा के बेटे ऐशी राम के नाम पर 2.9/1/2 मानक एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र की अनुमति दी गई थी और उनके दावे को जैसा कि याचिकाकर्ता ने 6 नवंबर, 1995 को अनुमति दी थीहिसार से अंबाला जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था।, यह मामला उनके निर्देशों के बावजूद संयुक्त सचिव, पुनर्वसन के समक्ष नहीं रखा गया था और बल्कि तहसीलदार मुख्यालय ने आदेश दिया कि माननीय राजस्व मंत्री की इच्छा के अनुसार बिक्री इकाई अंबाला

में आबंटनकर्ता को इतना क्षेत्र प्रदान किया जाए।यह 26 से अधिक मामलों में था किभूमि के आबंटन के लिए फाइलों का रिकॉर्ड सीधे याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी को प्रस्तुत किया गया था और कई मामलों में जहां एल. आर. और उनके वकीलों के बीच, या वकीलों और आबंटनकर्ताओं के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी द्वारा स्वयं एक बिक्री इकाई से दूसरी बिक्री इकाई में स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कथित रूप से उपरोक्त अनियमितताओं को करके और अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करके अवैध रूप से करोड़ों रुपये जमा किए थे।

(10) याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच. एस. हुड्डा ने तर्क दिया कि यह मामला हिरासत में पूछताछ के लिए मामूली है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि एफ. आई. आर. में निहित आरोपों से याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। शेष तीन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलदेव सिंह ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नरिंदर कुमार, हरीश कुमार और राजिंदर कृष्ण के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।दूसरी ओर, हरियाणा के महाधिवक्ता श्री एम. एल. सरीन ने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत की रियायत के लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे के साथ साजिश करके सरकार के करोड़ों रुपये हड़प लिए हैं और उन्होंने खुद को गलत लाभ देने और राज्य के खजाने और वास्तविक दावेदारों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भूमि का आबंटन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।उन्होंने आगे कहा कि इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रयोग की गई कार्यप्रणाली का *पता लगाने* के लिए याचिकाकर्ताओं की हिरासत में पूछताछ ही एकमात्र प्रभावी विकल्प है।

(11) याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी द्वारा कथित रूप से राजस्व मंत्री के रूप में उनके आधिकारिक दर्जे के दुरुपयोग से किए गए अपराध से संबंधित हैं।अब तक यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में, हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, क्योंकि संरक्षित पूछताछ केवल एक अनुष्ठान है।गुरबख्श सिंह *सिबिया बनाम पंजाब* राज्य *(1) मामले में* माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने न्यायालय को निम्नलिखित शब्दों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक विवेक का बुद्धिमानी से प्रयोग करने के लिए आगाह किया हैः—

> "न्यायिक शक्ति का एक बुद्धिमान अभ्यास अनिवार्य रूप से उन बुरे परिणामों का ध्यान रखता है जो इसके असंयमित उपयोग से निकलने की संभावना है।प्रत्येक प्रकार का न्यायिक विवेकाधिकार, चाहे उस मामले की प्रकृति कुछ भी हो, जिसके संबंध में इसका प्रयोग करने की आवश्यकता है, का उपयोग उचित सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।वास्तव में, उस संदर्भ के बारे में जागरूकता जिसमें विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना आवश्यक है और इसके उपयोग से

(1) 1980(2) एस. सी. सी 565

यथोचित रूप से पूर्वानुमेय परिणाम।

न्यायिक विवेकाधिकार के विवेकपूर्ण प्रयोग की विशिष्टता में, किसी को अग्रिम जमानत देने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिएः—

(12) वर्तमान मामले जैसे मामलों में, जिस प्रमुख कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह है आपराधिक साजिश का परिमाण और जिस सावधानी के साथ इसे लागू किया गया था।तत्काल मामलों में, याचिकाकर्ता आनंद सिंह डांगी ने कथित तौर पर विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के आबंटन के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं को अनदेखा कर दिया और कथित तौर पर करोड़ों रुपये एकत्र किए।इन सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *परस्पर संबंध* दिखाने वाले आरोपों और वे आपराधिक साजिश में भागीदार होने के कारण, अग्रिम जमानत की रियायत के उद्देश्य से उनके मामलों पर संदर्भ से बाहर विचार करना सुरक्षित नहीं है।एफ. आई. आर. में निहित आरोप शेष तीन याचिकाकर्ताओं के मामलों को उनके अन्य सहयोगियों से उनके द्वारा कथित रूप से संयुक्त रूप से किए गए अपराधों के लिए अलग करने का आह्वान नहीं करते हैं।उनकी अभिरक्षा में पूछताछ यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि उनके पक्ष में मुख्तारनामा किसने निष्पादित किया था और उनके द्वारा मुख्तारनामा को कहां प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जालसाजी की गई थी और यह भी पता लगाने के लिए कि कैसे राजिंदर कृष्ण सहायक पंजीयक अपने दावे की शुद्धता या मुख़्तारनामा की पुष्टि नहीं करके झूठे मामलों को संसाधित करने के उनके मंसूबों का शिकार हो गए।

(13) आनंद सिंह डांगी के खिलाफ आरोप आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के अलावा आय के ज्ञात स्रोतों के साथ बेनामी संपत्ति जमा करने, राज्य को धोखा देने, जिसके हितों की रक्षा करना उसका कर्तव्य था,धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और जाली दस्तावेजों जिन्हें जाली माना जाता था को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के आरोप हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार आदि। ये सभी गंभीर अपराध हैं।आपराधिक साजिश का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हो सकता है और इसी तरह के मामलों में आरोपी व्यक्तियों के कृत्यों और आचरण से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए।ऐसे अभियुक्तों की अभिरक्षा में पूछताछ जानकारी और ऐसी सामग्री एकत्र करने के लिए आवश्यक है जो अन्यथा छिपी रहती है।उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के मामलों में, अग्रिम जमानत का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आरोपी व्यक्तियों को इस तरह की रियायत के लिए कुछ बहुत ही मजबूर करने वाली परिस्थितियाँ नहीं बनाई जाती हैं।चूंकि आरोप हैं, कुछ मामलों में जहां आबंटनकर्ताओं को याचिकाकर्ता के कहने पर भूमि आवंटित की गई है, यह पता लगाया जाना है कि इन आबंटन में वास्तविक लाभकर्ता कौन है।यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में राज्य द्वारा पैकेज सौदे के दौरान खरीदी गई भूमि स्वयं आवंटित की गई है। इन सभी आरोपों के लिए याचिकाकर्ताओं से प्रभावी पूछताछ की आवश्यकता है ताकि फर्जी आवंटियों को भूमि आबंटन में याचिकाकर्ताओं और पुनर्वास विभाग के संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता औरऐसे आबंटन से आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए गलत लाभ का पता लगाया जा सके। याचिकाकर्ताओं के वकील

का तर्क है कि एफ.आई.आर. विस्तृत तथ्यों की जांच करने के बाद दर्ज की गई है जिसमें हर मामले पर गौर किया गया है और याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ उद्देश्यहीन है क्योंकि उनसे कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है, इसमें कोई दम नहीं हैं। कानून के तहत आबंटन प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं व्यक्तियों को भूमि के आबंटन में स्पष्ट अनियमितताओं/अवैधताओं के आलोक में उनका तर्क भी आधारहीन है।मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया एफ. आई. आर. में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के आपसी संबंध का संकेत देते हैं।

(14) ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जमानत की रियायत का कोई मामला नहीं बनता है ,तदनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा